

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग),

भारत सरकार

‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्ली, कार्तिक 10, 1945

बुधवार, नवंबर 01, 2023

स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के दौरान रक्षा विभाग के सभी चिन्हित लक्ष्यों का 100% निपटान के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण

रक्षा विभाग ने स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 का सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। प्रारम्भिक चरण (15-29 सितंबर, 2023) के साथ-साथ कार्यान्वयन चरण (02-31 अक्टूबर, 2023) दोनों को शामिल करने वाले विशेष अभियान में स्वच्छता को दैनिक आदत के रूप में शामिल करने पर जोर देने के साथ विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि एक स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल सुनिश्चित किया जा सके जो अंततः उत्पादकता में वृद्धि के रूप में परिणत होता है। अभियान के दौरान, अभिलेख प्रबंधन पद्धतियों की समीक्षा की गई जिसमें विभागीय रिकार्ड रूम का निरीक्षण शामिल था। चूंकि इस वर्ष रक्षा प्रतिष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, इसलिए तैयारी चरण के दौरान उच्चतम स्तर पर सभी संबंधित संगठनों की कार्य योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठकें आयोजित की गईं।

रक्षा विभाग ने विभिन्न मापदंडों में सभी अमान्य लक्ष्यों का 100% निपटान हासिल कर लिया है। कार्यान्वयन चरण के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर सांसदों के कुल 88 संदर्भों और 1088 लोक शिकायतों का निपटान किया गया है, जिसमें 28 नियमों/प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी शामिल है। 35,660 वास्तविक फाइलों की समीक्षा की गई है जिनमें से 26,948 फाइलों को हटा दिया गया है। उपलब्ध संसाधनों के लाभकारी उपयोग और कबाड़ के निपटान से राजस्व के सृजन पर इस अभियान के व्यापक जोर को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने साउथ ब्लॉक में फर्नीचर स्कैप और अप्रचलित आईटी उपकरणों जैसे फोटोकॉपियर मशीनों के निपटान के माध्यम से 5,34,000 रुपये का राजस्व उत्पन्न किया है। इसके अलावा इस अभ्यास के दौरान 1,59,351 वर्ग फुट जगह भी खाली कराई गई है। मंत्रालय ने वाहनों की नीलामी के माध्यम से 55 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व भी अर्जित किया है।

इसके अलावा, 3066 स्थानों पर जन-केंद्रित जुड़ाव के साथ सहवर्ती अखिल भारतीय स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। ये स्थान विभिन्न संगठनों जैसे रक्षा लेखा महानियंत्रक, सीमा सड़क संगठन, सैन्य अस्पताल, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, भारतीय तटरक्षक बल, सैनिक स्कूल, कैंटीन स्टोर विभाग और छावनियों से संबंधित हैं।

यह भी रिकॉर्ड करना सार्थक हो सकता है कि विशेष अभियान 3.0 के दौरान रक्षा विभाग की यात्रा कई मील के पथर से भरी रही है। अभियान के दौरान लागू की गई सर्वोत्तम प्रथाओं के हिस्से के रूप में, छावनी बोर्ड देहरादून ने पॉलिथीन कचरे के निपटान के लिए देहरादून छावनी क्षेत्र में "पॉलिथीन कचरा बैंक" शुरू किया। पॉलिथीन अपशिष्ट यानी चिप्स रैपर, पॉलिथीन पैकिंग बैग, पॉलिथीन बोरे आदि लोगों से 03 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे जाते हैं। छावनी क्षेत्र में तीन स्थलों पर पॉलिथीन कचरा बैंकों के लिए संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं। एकत्र किए गए पॉलिथीन कचरे का उपयोग उच्च घनत्व कम्पोजिट पॉलिमर (एचडीसीपी) टाइल्स, बोर्ड आदि के निर्माण के लिए किया जाता है।

सीमा सड़क संगठन ने स्टील स्लैग का उपयोग करके सड़क का निर्माण किया है - जो इस्पात निर्माण का एक अपशिष्ट उपोत्पाद है। अरुणाचल प्रदेश में एक किलोमीटर लंबी जोरम-कोलोरियांग सड़क का निर्माण अपशिष्ट से धन पहल के हिस्से के रूप में 1200 मीट्रिक टन स्टील स्लैग का उपयोग करके किया गया है।

अभियान के दौरान साउथ ब्लॉक में एक पूर्व अप्रयुक्त कमरे को कचरे से साफ किया गया और पुनर्निर्मित किया गया और इसे "लेडीज रूम" में बदल दिया गया, जहां महिला कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार खुद को तरोताजा कर सकती थीं। इसके अलावा, साउथ ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर एक विशेष स्थान से कचरा साफ किया गया है, जो पहले एक निष्क्रिय विभागीय कैंटीन थी। अंतरिक्ष का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस तरह के सकारात्मक हस्तक्षेप अनुकरण किए जाने योग्य हैं।

विभाग ने सुशासन सप्ताह, 2023 के दौरान इनमें से कुछ पहलों/प्रथाओं को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव किया है।

एबीबी/ स्वामी